आक्रामक कूटनीति का मामला: भारत-पाकिस्तान संबंधों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

द हिन्दू

लेखक- अमित बरुआ (वरिष्ठ सहायक संपादक)

12 मार्च, 2019

"भारत की प्रतिक्रियाएँ आतंकवादी समूहों के एजेंडे के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं हो सकती हैं।"

पाकिस्तान और भारत काफी हद तक असामान्य राष्ट्र हैं। जिस तरह भारत के बालाकोट आतंकी शिविर पर बमबारी के बाद संघर्ष बंद हो गया था, पाकिस्तान ने 5 मार्च को आरोप लगाया था कि इसने अपने जल सीमा में एक भारतीय पनडुब्बी के प्रवेश को विफल कर दिया है। हांलाकि, भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठे प्रचार में लिप्त है। उसी शाम, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि भारत में उसके उच्चायुक्त, सोहेल महमूद, दिल्ली लौटते ही भारत के साथ करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत करेंगे। यह एक संकेत था कि आधिकारिक तौर पर तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने करतारपुर की वार्ता की पुष्टि की और भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को भी इस्लामाबाद वापस भेज दिया।

5 मार्च की सुबह और शाम की घटनाओं से जनता के बीच वास्तविक भ्रम पैदा हो सकता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पाकिस्तान द्वारा सुबह में दिया गया बयान अपने घरेलू दर्शकों के लिए था और शाम में दिया गया बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक संकेत था कि भारत के साथ आगे बढ़ने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी।

तनाव को कम करना

यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में प्रमुख शक्तियों की भागीदारी का पहला स्पष्ट संकेत दिया था। अमेरिका के अलावा, चीनी और सउदी भी भारत-पाकिस्तान के समीकरण के बीच दिलचस्पी ले रहे थे।

दोनों सरकारों के लिए स्कोर बराबर का रहा, जहाँ एक ने एफ-16 को मार गिराया तो दूसरे ने मिग-21 को मार गिराया, इसलिए अब वे वैश्विक चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बात की जाए तो ऑपरेशन बालाकोट ने उन्हें अपनी चुनावी रैलियों में एक बेहतर हथियार प्रदान किया है।

तनाव के चरम पर होने और पाकिस्तान के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लेने के बाद, करतारपुर वार्ता पर मोदी सरकार का निर्णय विचित्र लगता है। लेकिन यह दो उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे करते हुए पंजाब में वोट जीतने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उचित होने के रूप में दिखाता है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत, बालाकोट में अपनी पूर्वानुमानित हमला करने के बावजूद बच कर निकल आया क्योंकि पाकिस्तान के साथ-साथ उसके नागरिकों का भी का यह कहना कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे कट्टर समूहों से उसका कोई लेना देना नहीं है। हांलाकि, (JeM) ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया प्रचार, नकली वीडियो, आंतरिक दबाव और दोनों ओर से हो रहे गंदे वाद-विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान एक बड़े से संघर्ष से बच गए हैं।

वाजपेयी वर्ष

भारत-पाकिस्तान परमाणु निवारक को जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा परीक्षण के लिए पहली बार रखा गया था, जिन्होंने 11 और 13 मई, 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के जवाब में पाकिस्तान द्वारा सार्वजनिक रूप से परमाणु परीक्षण करने के बाद कारगिल में घुसपैठ की योजना बनाई थी।

जैसे-जैसे भारत ने पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री (Northern Light Infantry), जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे। को कारगिल की ऊंचाइयों से हटाना शुरू किया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर दो मिग विमानों के नुकसान के बाद नियंत्रण रेखा के पार जाकर भारतीय वायु सेना का उपयोग करने का भारी दबाव डाला जा रहा था। लेकिन वाजपेयी ने सार्वजनिक और भारतीय वायुसेना के दबाव के सामने मजबूती से काम लिया। कारगिल संघर्ष के दौरान, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश सचिव शमशाद अहमद और मंत्री राजा जफर-उल-हक ने स्पष्ट किया कि इसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उपयोग के लिए भी है। कारगिल के दौरान पाकिस्तान के आचरण ने देश को गैर-जिम्मेदार बताया और एलओसी का सम्मान करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय बयान भी सामने आने लगे।

पाकिस्तान, भारत के खिलाफ अपनी परमाणु क्षमता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से काफी आगे बढ़ गया है और कोई भी 'सैन्य

प्रतिष्ठान' वहां जीवित नहीं रह सकता है यदि वह भारत के साथ बराबरी करने में असमर्थ है।

1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, 2001 में संसद हमले के बाद और 2008 में मुंबई हमले के बाद, भारत के दो प्रधानमंत्रियों के पास प्रतिशोध का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया।भारत ने धैर्य के साथ अपने जिम्मेदार प्रकृति को दर्शाया, जो पाकिस्तान की कमजोर विश्वसनीयता के विरोध में था।

यह भारत की गुप्त क्षमताओं की क्षमा करने वाली स्थिति पर एक टिप्पणी है जो पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क के प्रमुख आंकड़ों का संचालन नहीं करता है। 1999 में IC-814 अपहरण और हरकत-उल-मुजाहिदीन के संस्थापक, फजलुर रहमान खलील, को अभी हाल ही में वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर देखा गया था। यहाँ जमीनी हकीकत यह है जेईएम और लश्कर पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, उसे भारतीय दबाव से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से प्रतिबंधों के खतरे से तय किया जा रहा है। यदि प्रतिबंधों का खतरा कम हो जाता है, तो ये कार्य समाप्त हो जाएंगे।

वार्ता और सिर्फ वार्ता

आतंकवादी समूहों के लिए एक पारंपरिक प्रतिक्रिया नेक इरादे का प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन उनकी क्षमताओं को कम करने के लिए बहुत कम है। अप्रकट क्षमता और लगातार कूटनीति से जुड़ी गुप्त क्षमताएँ ऐसी कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है।

मोदी सरकार की कश्मीरियों तक पहुंचने में असमर्थता और हुर्रियत नेतृत्व के खिलाफ उसकी कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब अलगाववादियों ने जनता पर से नियंत्रण खो दिया है। इसने कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी रैंक में शामिल होने के लिए एक उपजाऊ मैदान भी बनाकर दिया है।

भारत की प्रतिक्रियाएँ आतंकवादी समूहों के एजेंडे के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं हो सकतीं, चाहे उनके कार्य कितने भी क्रूर हों। अपने मूल में आक्रामक कूटनीति के साथ एक शांत, परिपक्व, सूचित और दीर्घकालिक रणनीति, जो भारत की आर्थिक ताकत का लाभ उठाती है, वह पाकिस्तानी धरती से आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए देश की सबसे अच्छी शर्त बनी हुई है।

GS World टीम...

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पेरिस में सप्ताह-भर चलने वाली अपनी सार्वजनिक बैठक के अंत में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट अर्थात् संदेहास्पद सूची में रखने का निर्णय लिया है।
- हांलाकि, भारत चाहता था कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने के कारण ब्लैकलिस्ट किया जाए अर्थात् काली सूची में डाला जाए।
- वर्ष 2012 में पहली बार पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया था और 2015 तक इसमें रहा था। 29 जून, 2018 को एफएटीएफ ग्रे में दूसरी बार पाकिस्तान को सूचीबद्ध किया

क्या है?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1989 में G7 की पहल पर स्थापित किया गया है।
- यह एक नीति-निर्माता निकाय है जिसका कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी एवं नियामक सुधार लाने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति तैयार करना है।
- इसका सचिवालयपेरिस के व्ब्ब्क मुख्यालय भवन में स्थित है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग, आतंकवादियों को धनराशि मुहैया करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को खतरे में डालने जैसी अन्य कार्रवाईयों को रोकने हेतु कानूनी, नियामक और संचालन से संबंधित उपायों के लिए मानक निर्धारित करना है।

ग्रे लिस्ट में डालने का निहितार्थ

- FATF की निगरानी सूची में पाकिस्तान को डाले जाने से उसकी अर्थव्यवस्था को घातक क्षति होगी और विदेशी निवेशकों और कंपनियों को उस देश में व्यवसाय करने में और भी कठिनाई होगी।
- कुछ वित्तीय संस्थाएँ पाकिस्तान के बैंकों के साथ लेन-देन करने से बचना चाहेंगी।
- FATF की निगरानी सूची में डाले जाने का कोई प्रत्यक्ष कानूनी निहितार्थ नहीं होता, किन्तु इससे यह होता है कि नियामक निकाय और वित्तीय संस्थाएँ कुछ अधिक ही जाँच-पड़ताल करती हैं जिसके फलस्वरूप व्यापार और निवेश ठंडा पड़ सकता है और लेन-देन की लागत बढ़ सकती है।

ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या हैं?

- FATF देशों के लिए दो अलग-अलग सूचियाँ संधारित करता है। पहली सूची में वे देश आते हैं जहाँ मनी लॉन्डरिंग जैसी कुप्रथाएँ तो हैं परन्तु वे उसे दूर करने के लिए एक कार्य योजना के प्रति वचनबद्ध होते हैं।
- दूसरे प्रकार की सूची में वे देश हैं जो इस कुरीति को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनमें से पहली सूची को ग्रे लिस्ट और दूसरी को ब्लैक लिस्ट कहते हैं।
- एक बार जब कोई देश ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो FATF अन्य देशों को आह्वान कर उनसे कहता है कि ब्लैक लिस्ट में आये हुए देश के साथ व्यवसाय में अधिक सतर्कता बरतें और यदि आवश्यक हो तो उसके साथ लेन-देन समाप्त ही कर दें।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. करतारपुर कॉरीडोर सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
   2. जम्मू-कश्मीर में पुलवामा हमला आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**

   1. Kartarpur corridor is considered the holy place for Sikhs.
   2. The Pulwama attack in Jammu-Kashmir carried out by Jaish-e-Mohammad terroist organisation.

   Which of the following statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में हुए पुलवामा आतंकवादी हमले के पश्चात् पाकिस्तान के प्रति भारतीय कूटनीतिक दृष्टिकोण में आये बदलाव की समीक्षा कीजिए।

Q. Analyse the change into the Indian diplomatic approach towards Pakistan after recent Pulwama terroist attack.

(250Words)

नोट : 11 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence